भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 205
दिनांक 03 अगस्त, 2023

प्राकृतिक गैस की मांग

†*205. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे :
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अगले कुछ वर्षों में भारत की प्राकृतिक गैस की मांग में काफी वृद्धि होने की संभावना है जिससे अन्य देशों से गैस आयात करने हेतु काफी दबाव होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार/भारतीय तेल कंपनियां विदेशों से सस्ती गैस प्राप्त करने के लिए इराक में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) टर्मिनल बनाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में इराक के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार द्वारा इराक में द्रवीकरण संयंत्र स्थापित करने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का एक दल विशेष इराक भेजा गया है/भेजे जाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार की ऊर्जा की सस्ती खरीद के लिए अन्य देशों से भी ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करने या उनमें एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (च): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'प्राकृतिक गैस की मांग' के बारे में संसद सदस्य श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे और श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा दिनांक 03.08.2023 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 205 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) सरकार द्वारा ऊर्जा मिश्र में प्राकृतिक गैस की अभी भी लगभग 6% की हिस्सेदारी को वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 15% तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार द्वारा इस दिशा में विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं जिसमें राष्ट्रीय गैस ग्रिड पाइपलाइन का विस्तार करना, नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क का विस्तार करना, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) टर्मिनलों की स्थापना करना, किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विकल्प (सतत) पहल आदि शामिल हैं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने देश भर में लगभग 33,592 किलोमीटर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क को प्राधिकृत किया है जिसमें से 23,173 किलोमीटर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रचालन में है और कुल 12,206 किलोमीटर लम्बाई की पाइपलाइने निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

देश भर में सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए देश की करीब 98% आबादी और कुल 88% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करते हुए 28 राज्यों/सं.शा.क्षेत्रों के करीब 630 जिलों में फैले 300 भौगोलिक क्षेत्रों (जीएज) को पीएनजीआरबी ने प्राधिकृत किया है। दिनांक 31.05.2023 की स्थिति के अनुसार 5,767 सीएनजी स्टेशन चालू किए गए हैं और सीजीडी कम्पनियों द्वारा 1.12 करोड़ पाइप्ड प्राकृतिक गैस (घरेलू) कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

प्राकृतिक गैस का सकल घरेलू उत्पादन वर्ष 2020-21 में 28,672 एमएमएससीएम से लगभग 20% बढ़कर वर्ष 2022-23 में 34,450 एमएमएससीएम हो गया है। भारत ने वर्ष 2022-23 के दौरान 26,304 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर (एमएमएससीएम) तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का आयात किया था। वर्तमान में, देश में लगभग 47.7 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष (एमएमटीपीए) की संयुक्त क्षमता के साथ 7 एलएनजी पुनर्गैसीकरण टर्मिनल प्रचालन में हैं।

घरेलू गैस का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने उत्पादन हिस्सेदारी व्यवस्था के स्थान पर राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्था अपनाते हुए अन्वेषण रकबे प्रदान करने के निमित्त दिनाँक 30 मार्च, 2016 को हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसें सग नीति (एचईएलपी) अधिसूचित की थी। सरकार ने आगे दिनाँक 28 फरवरी, 2019 को नीतिगत सुधारों को अधिसूचित किया है जिसमें "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" को बढ़ावा देने के लिए कई प्र िया एवं अनुमोदनों में छूट प्रदान की गई है, श्रेणी II एवं III प्रकार के बेसिनों से अप्रत्याशित लाभ के अलावा राजस्व हिस्से को हटा लिया गया था, गहरे एवं अत्यधिक गहरे ब्लॉकों के लिए 7 वर्षों का रायल्टी हॉलिडे, गहरे समुद्री क्षेत्र एवं अत्यधिक गहरे समुद्री क्षेत्र ब्लॉकों के लिए छूटप्रा रॉयल्टी दर और प्राकृतिक गैस के विपणन एवं मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता के साथ क्षेत्रों के शी मौद्रीकरण के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने विभिन्न अपशिष्ट /बायोमास स्रोतों से संपीडित जैव गैस (सीबीजी), जो प्राकृतिक गैस को प्रतिस्थापित कर सकेगी, के उत्पादन के लिए ईकोसिस्टम स्थापित करने एवं प्राकृतिक गैस के साथ इसका उपयोग बढ़ाने के प्रयोजन से दिनाँक 1 अक्टूबर, 2018 को "किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विकल्प (सतत)" की शुरूआत भी की है। अब तक, 48 सीबीजी संयंत्र चालू किए गए हैं।

(ग) से (च) घरेलू बाजार में तेल और गैस की बढ़ती माँग को देखते हुए ईराक/अन्य देशों में निवेश के अवसर तलाशने के लिए भारतीय कम्पनियाँ तैयार हैं।

***